

समाधान केंद्र बने सिर्फ औपचारिक त्यवस्था, सुधार कराने जाना पड़ रहा भोपाल

नवभारत न्यूज
बैतूल, 5 अगस्त. जिला मुख्यालय पर संचालित पेंशन कार्यालय बंद कर दिये गये हैं। जिसके कारण अब पेंशनरों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल शासन ने पेंशन जिला पेंशन कार्यालय बंद, भटक रहे पेंशनर्स स्टॉप कम होने से बढ़ी दिक्कतें

व्यवस्था को आधुनिक और केंद्रीकृत बनाने के उद्देश्य से जिलों के पेंशन कार्यालय बंद कर दिए। इसका सबसे बड़ा खामियाजा सेवानिवृत्त कर्मचारी भुगत रहे हैं। पहले जिन कार्यों का निराकरण जिला मुख्यालय पर कुछ दिनों में हो जाता था, अब उन्हीं के लिए भोपाल

के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे बुजुर्ग पेंशनरों पर आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। नई व्यवस्था में ग्रेच्युटी और पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी भी अलग-अलग विभागों को सौंपी है। ग्रेच्युटी का भुगतान पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय भोपाल द्वारा किया जा रहा है। मासिक पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी एसबीआई को केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेल को दी है। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो पेंशनरों को दो अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना पड़ता है। पहले दोनों का एक कार्यालय से होने से समस्याओं का समाधान अपेक्षाकृत आसान था। कुल मिलाकर, पेंशन व्यवस्था के केंद्रीकरण का उद्देश्य भले ही प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर यह व्यवस्था सेवानिवृत्त कर्मचारियों के



लिए राहत के बजाय नई परेशानियों का कारण बनती दिखाई दे रही है। समाधान केन्द्र में भी नहीं हो रहा समाधान : जिला मुख्यालयों पर शुरू किए गए समाधान केंद्र भी पेंशनरों की समस्याओं का प्रभावी समाधान नहीं कर पा रहे हैं। पहले प्रत्येक जिले में जिला पेंशन

कार्यालय संचालित होते थे, जहां पेंशन प्रकरण तैयार करने से लेकर पीपीओ (पेंशन भुगतान आदेश) जारी करने, बैंक को प्रकरण भेजने और पेंशन भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया एक ही स्थान पर पूरी हो जाती थी। अब इन कार्यालयों को बंद कर सभी कार्य भोपाल स्थित

पेंशन संचालनालय की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेल को सौंप दिए गए हैं। बैतूल में अब केवल एक समाधान केंद्र संचालित है, जहां सीमित स्टाफ के कारण पेंशनरों को अपेक्षित सहायता नहीं मिल पा रही है।

स्टाफ कम होने से बढ़ी दिक्कत

: पहले जिला पेंशन कार्यालय में एक पेंशन अधिकारी, तीन सहायक पेंशन अधिकारी, दो लिपिक और दो भृत्य पदस्थ थे। अब समाधान केंद्र में केवल एक सहायक पेंशन अधिकारी, दो निम्न श्रेणी लिपिक और दो नृत्य ही कार्यरत हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या घटने से स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान लगभग ठप हो गया है। पेंशनरों का कहना है कि जिस व्यवस्था को, प्रक्रियाओं को सरल और तेज करने लागू किया गया था, वहीं अब

पेंशनरों के लिए नई मुश्किलों का कारण बन गई है। छोटी-छोटी

कमियों को दूर कराने भी पेंशनरों को भोपाल जाना पड़ रहा है।

कमियों को दूर करने जाना पड़ता है भोपाल

जिला पेंशन कार्यालय बंद होने से अब पेंशनरों को छोटी-छोटी कमियों को दूर करने के लिए भी पेंशनरों को भोपाल जाना पड़ रहा है। अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मचारी बुजुर्ग हैं, ऐसे में बार-बार राजधानी की यात्रा उनके लिए आर्थिक और शारीरिक रूप से कठिन साबित हो रही है। पेंशनरों का कहना है कि जिला मुख्यालय पर समाधान केन्द्र जरूर खोले गये हैं, लेकिन यहां उनकी समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उन्हें पेंशन से संबंधित जानकारी के लिए भोपाल तक दौड़ लगानी पड़ती है। पेंशनरों का कहना है कि उम्र दराज होने के कारण बार-बार भोपाल आना-जाना उनके लिए हमेशा संभव नहीं होता है और मानसिक-आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

प्रकरण कहां लबित, नहीं मिल पाती जानकारी

नई व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पेंशनरों को यह तक पता नहीं चल पाता कि उनका प्रकरण किस स्तर पर लंबित है। पहले यदि किसी दस्तावेज में कमी या आपत्ति होती थी तो जिला कार्यालय से तुरंत सूचना मिल जाती थी या प्रकरण संबंधित विभाग को वापस स्थानीय स्तर पर समस्याओं का निराकरण लगभग ठप हो गया है। नई व्यवस्था के तहत अब संबंधित विभाग के डीडीओ (ड्राइंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफिसर) के लॉगिन से पेंशन प्रकरण सीधे भोपाल स्थित केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेल भेजा जाता है। वहां से जांच और स्वीकृति के लिए प्रकरण किसी भी जिले में भेजा जा सकता है। स्वीकृति मिलने के बाद अंतिम कार्रवाई फिर भोपाल में होती है। पहले यही पूरी प्रक्रिया जिला पेंशन कार्यालय में पूरी हो जाती थी, जिससे समय भी कम लगता था और आवेदक को अपने प्रकरण की स्थिति की जानकारी भी आसानी से मिल जाती थी।

एक नजर में

औद्योगिक क्षेत्र का कलेक्टर ने किया निरीक्षण बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने ग्राम चोरडोंगरी पहुंचकर माइक्रो स्मॉल इंटर्प्राइजेंज वलस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा औद्योगिक विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंचने के लिए काफी समय से लंबित एप्रोच रोड की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के इच्छुक निवेशकों, उपलब्ध सुविधाओं एवं विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र धीरज मंडलेकर, जिला खनिज अधिकारी मनीष पालेवाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

13 अगस्त को होगा मेगा सवैच्छिक रक्तदान अभियान

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार जेष्ठ कौलेज ऑडिटोरियम बैतूल में 13 अगस्त 2026 को रक्ताजलि-एक रक्तदान, रात के नाम अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय मेगा सवैच्छिक रक्तदान शिबिर का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने जिले के सभी विभागाध्यक्षों से अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विभाग अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें तथा सलग्न गुगल फॉर्म के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में उनका पंजीयन कराएं।

मेटॅनॅस के कारण बंद रहेगी बिजली

बैतूल। बिजली कंपनी द्वारा 6 अगस्त को मेटॅनॅस कार्य के चलते 11 कंहेरी सदर फौडर की विद्युत प्रवाह प्रभावित रहेगी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बैतूल शहर छात्र-2 के प्रबंधक ने बताया कि गुरुवार को सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक सदर सब स्टेशन के एमपीडीबी कॉलोनी, अग्रिमहोत्री कॉलोनी, सताल आश्रम, प्रतिभा वार्ड, सुपर किराना, सिंडिकेट बैंक, एसबीआई बैंक, गेंदा चौक, ब्रह्माकुमारी आश्रम, मानस नगर, आईटीआई, एफसीआई गोदाम, विनायक रिजिडेंसी आदि क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी।

पत्रकारवार्ता ▶ प्रत्यक्ष प्रणाली से छत्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फेंस

जल्द ही शुरू होगा एनएसयूआई का निशुल्क सदस्यता अभियान

बैतूल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा छत्र संघ चुनाव कराए जाने के संबंध में दिए गए आदेश के बाद एनएसयूआई बैतूल के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रोहन सिंह ठाकुर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर प्रदेश सरकार से छत्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रोहन सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली पाठशाला हैं और छात्रों को अपने प्रतिनिधि सीधे चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लिंगदोह समिति की अनुशंसाओं का पालन करते हुए प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में शीघ्र छत्र संघ चुनाव की तिथि



घोषित की जाए तथा चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाए जिसको लेकर एनएसयूआई द्वारा निशुल्क सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और छात्रों को संगठन से जोड़ा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से छत्र संघ चुनाव नहीं होने के कारण छात्रों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से

कराने में देरी करती है, तो एनएसयूआई प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। उन्होंने सरकार से जल्द चुनाव कार्यक्रम घोषित करने और छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान करने की मांग की। एनएसयूआई के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रोहन सिंह ठाकुर ने एबीवीपी के द्वारा जिले में लगातार की जा रही गुंडागर्दी को लेकर चिंता जताई है और आरोप लगाया है कि एबीवीपी कार्यकर्ता आए दिन कॉलेज में घुसकर छात्रों और शिक्षकों के साथ अभद्रता कर रहे हैं,एनएसयूआई उन सभी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग करते हैं जो कॉलेज का माहौल

खराब कर रहे हैं।जिलाध्यक्ष रोहन सिंह ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि एबीवीपी शासकीय और निजी स्कूलों में जबरदस्ती घुस कर बच्चों से शुल्क वसूल रही है और छात्रों को अपना सदस्य बना रही है जबकि स्कूलों में राजनैतिक गतिविधिया प्रतिबंधित होती है उसके बावजूद स्कूल प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से कांग्रेस जिला प्रवक्ता लवलेश बब्बा राठौर, जिला उपाध्यक्ष हर्षवर्धन धोटे, जिला महासचिव मोन्ू बडोनिया, दानिश पारेख, मोहसिन खान, एनएसयूआई के रामकुमार नागवंशी, नितिन बिस्वास, आसिफ अंसारी एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।